आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 11.04.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। सोलह सुपर जोन में बांटा गया यात्रा क्षेत्र। सात हजार पुलिसकर्मी होंगे तैनात।
- रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सिरोहबगड़ भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा– यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के साथ सुगमता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता।
- केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। विभिन्न विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
- न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और जनोन्मुख बनाने की दिशा में राजधानी देहरादून में दो दिवसीय नॉर्थ जोन सम्मेलन। देशभर के न्यायाधीश और विधिक विशेषज्ञ अपने सुझाव साझा करेंगे।

चारधाम सुरक्षा

चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को चाक–चौबंद किया गया है। यात्रा में लगभग सात हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और पूरे यात्रा क्षेत्र को 16 सुपर जोन में बांटा किया गया है। गढ़वाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षण राजीव स्वरूप को चारधाम यात्रा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प सेंटर, हॉल्टिंग प्वाइंट और आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट मोड पर तैनात रहेंगी। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में चारधाम और हेमकुण्ड साहिब यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में यात्रा मार्गों, धामों और संबंधित जिलों में सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि दो एडीजी और चार आईजी स्तर के अधिकारी चारों धामों सहित यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। "एकीकृत चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम" से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटीएस टीमों की तैनाती के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी, ड्रोन और हाई–टेक रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से यात्रा मार्गों और धामों की निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी नजर रखने और फर्जी वेबसाइटों और साइबर ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरे के उपयोग पर निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके।

केदारनाथ यात्रा/निरीक्षण

केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रा मार्ग पर स्थित संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र–सिरोहबगड़ का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सड़क को सुचारू बनाए रखने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक और मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यात्रा मार्ग पर

सुरक्षा के साथ–साथ सुगमता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को लगातार निगरानी करने और जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए।

उधर, उत्तरकाशी जिले के मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल, शौचालय, बिजली, रेन शेल्टर और रेलिंग की व्यवस्थाएं परखीं। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्रों की सक्रियता, एसडीआरएफ तैनाती और घोड़ा–खच्चरों के लिए चारा–पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ऑपरेशन प्रहार

देहरादून में "ऑपरेशन प्रहार" के तहत पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर टीमों की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस की टीमें सघन चेकिंग, सत्यापन और औचक छापेमारी कर रही हैं। होटल, पब और संदिग्ध गतिविधियों पर खास नजर रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री के 14 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा और निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है।

केंद्रीय राज्य मंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, अल्मोड़ा की बैठक, विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, सड़क, विद्युत और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी योजनाओं को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से लिया जाए। श्री टम्टा ने बताया कि पिछले बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों में प्रगति हुई है।

सम्मेलन

न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, समावेशी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राजधानी देहरादून में आज से दो दिवसीय नॉर्थ जोन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय "न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ बनाना" है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव सीमा हुंगराकोटी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में न्याय तक समान और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने, विधिक सेवा तंत्र को सुदृढ़ बनाने, कारागार सुधार, अंडरट्रायल बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा मानव–केंद्रित विधिक सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार–विमर्श किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न सत्रों में न्यायिक अधिकारी, विधिक विशेषज्ञ और नीति–निर्माता अपने अनुभव, नवाचार और सुझाव साझा करेंगे, जिससे न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में ठोस पहल संभव हो सकेगी।

ई–ऑफिस / कार्य□ाला

पौड़ी जिले में प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से पौड़ी में ई–ऑफिस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को ई–ऑफिस के माध्यम से कागजरहित कार्यप्रणाली अपनाने, फाइलों के त्वरित निस्तारण औरकार्यों की ऑनलाइन निगरानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट ने बताया कि ई–ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइल निर्माण, उनका ऑनलाइन संचालन, टिप्पणियों का आदान–प्रदान और शीघ्र निस्तारण संभव है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। प्रशिक्षण के दौरान ई–ऑफिस के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में

कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को ई–ऑफिस प्रणाली के उपयोग के लिए दक्ष बनाना तथा उनकी कार्यक्षमता व उत्पादकता में वृद्धि करना था। यह पहल शासन की डिजिटल इंडिया नीति के अनुरूप कार्यालयी कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।